

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू का आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज का दौरा प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर 50 हजार की घोषणा



मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू ने गत दिनों जिला शिमला के रामपुर में बादल फटने के कारण प्रभावित हुए समेज क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दृश्य में घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और आपदा प्रभावितों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 50 हजार रुपये और विद्युत पर आवासीय सुविधा के लिए तीन महीने तक किराए के लिए मिलेंगे पांच हजार प्रतिमाह कि समेज में 33

करने के निर्देश दिए ताकि इन परिवारों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पालशाला समेज के विद्यार्थियों से भेंट की, जिनके आठ सहायात्री इस घटना के बाद लापता हैं। आठवीं कक्ष के विद्यार्थी राखी और कार्तिक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस घटना से वे सदमें मैं हूं और उनका स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दाढ़िया बंधाते हुए उन्हें हौसला रखाने और परिवार का सहायोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर और बड़ा स्कूल फिर से निर्मित किया जाएगा। समेज की निवासी बिलाल देवी ने बादल फटने की घटना वाली भयावह रात को याद करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के दुःख-दर्द को साझा किया और आश्वासन दिया कि उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को विस्थापित प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

बेघर हुए लोगों को तीन महीने तक किराए के लिए मिलेंगे पांच हजार प्रतिमाह



सामना न करना पड़े। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना चरण दो को मिली वन स्वीकृति

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू ने गत दिनों कहा कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलावाही परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण-2 के तहत किन्नौर जिले में शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना

- ♦ 450 मेगावॉट विजली का होगा उत्पादन
- ♦ परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

के लिए लगभग 85 बीघा जमीन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2018 से लंबित थी। राज्य सरकार के विरुद्ध प्रयासों से यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण करने को इस भूमि की आवश्यकता थी। श्री सुख्खू ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत यह स्वीकृति केंद्र सरकार के

पास लंबे समय से विचाराधीन थी, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने कड़े प्रयास करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 19 मार्च, 2024 को प्रदान की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने आवश्यक नियमों व शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट सैद्धांतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंपी और केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति के लिए आगे है कि यागा ठाकुर से कहा कि शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना याज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 2012 में अर्वांड किया था, जो नवंबर, 2026 तक पूरा होना है। उन्होंने कहा कि परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए एक द्रांगमिशन लाइन बिछाई जा रही है। परियोजना का कार्य समय पर पूरा करने के लिए द्रांगमिशन की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई (शेष पृष्ठ 11 पर)

शानन परियोजना को वापिस लेने के लिए सरकार प्रयासरत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू ने गत दिनों विरिष के निर्माण किया गया था। वर्ष 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंद्र बहादुर और पंजाब के मुख्य अधियंता के बीच

सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश

99 वर्षों के लिए लीज समझौता हस्ताक्षित दुआ था। उस समय से ही इसका प्रशासनिक अधिकार पंजाब के पास है। इस वर्ष 2 मार्च, 2024 को लीज समाप्त हो गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र अधिकार में है और पंजाब सरकार को अविलम्ब इस परियोजना को लौटा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को लौटा देना चाहिए।

ग़ा़कुर सुखविंद्र सिंह सुख्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों के प्रायमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार इस परियोजना से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कानूनी कार्यालय को द्धान में स्वतंत्र हुए प्रदेश सरकार परियोजना को हासिल करने के लिए एक मजबूत मामला तैयार कर रही है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सरकार, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अबूर रतन, अंतिर्क मुख्य सचिव और अंकार चब्द शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव अरिद्वम चौधरी और अन्य विरिष अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

